



"रीवा जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाएं"

पूर्णमा कुमारे

शोधार्थी, वाणिज्य विभाग,
शास. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)



सारांश:-

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये औद्योगिक विकास की प्रथम आवश्यकता है। औद्योगिक विकास स्थानीय प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का सदपयोग, वस्तुओं का निर्माण एवं रोजगार के साधनों की वृद्धि होती है। यहाँ शेषणिक, चिकित्सकीय, यातायात, संचार, बीमा, बैंकिंग एवं विद्युत सिंचाई आदि सुविधाओं से युक्त है, जिस कारण औद्योगिक विकास की अपार सम्भावनाएं हैं। यद्यपि अनेक समस्यायें भी हैं, जैसे— जनजीवन का अभाव, कुशल प्रवर्तकों की कमी, पूँजी निर्माण में बाधा, इकाईयों की बढ़ती लागतें, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में विविलता, मशीनों एवं यंत्रों की अनुउपलब्धता, विपणन का अभाव, जनता में क्रय शक्ति की कमी आदि।

यद्यपि कुछ सुझाव भी हैं, जैसे— औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, मशीनों, यंत्रों, भूमि, जल की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता बनानी चाहिए, विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना एवं उद्यमियों को प्रोत्साहित करना आदि। रीवा जिले में शिक्षा एवं जागरूकता तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में रुचि दिखाई दे रही है। यदि शासकीय योजनायें इस हेतु कार्यान्वित की जाय तो निश्चित रूप से जिला उद्योग प्रधान जिला बन सकता है और साथ ही रीवा जिले का पर्याप्त विकास होगा।

मुख्य शब्द:— औद्योगिक विकास, शासकीय योजनायें, रीवा जिला।

प्रस्तावना:-

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये औद्योगिक विकास की प्रथम आवश्यकता होती है। औद्योगिक विकास स्थानीय प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों का सदपयोग, वस्तुओं का निर्माण एवं रोजगार के साधनों की वृद्धि होती है। पूँजी का सदपयोग विपणन क्रियाओं में तेजी व राजस्व में वृद्धि आदि। औद्योगिक विकास के कारण होते हैं। सरकारी नीतियों के अनुसार हर जिले का यथासंभव औद्योगिक विकास करने के प्रयास किये जा रहे हैं। छोटी, लघु, मध्यम एवं बड़ी औद्योगिक इकाईयों की स्थापना का समग्र क्षेत्र को औद्योगिक विकास से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। रीवा जिले में औद्योगिक विकास की अनेक संभावनाएं हैं। प्राकृतिक संसाधनों के साथ मूलभूत सुविधाओं जैसे— यातायात, संचार, बिजली, बीमा, बैंक आदि सुविधाएं प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। जिनका समुचित रूप से उपयोग करने पर रीवा जिला औद्योगिक विकास की दृष्टि से उन्नत जिला बन सकता है। प्रस्तुत शोध औद्योगिक संभावनाओं की खोज के लिये तैयार किया गया है।

शोध-प्रविधि :-

शोधकार्य को पूरा करने के लिये दोनों प्रकार के समकां का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक समकं विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं व सरकारी कार्यालयों, व्यक्तिगत साक्षात्कार कर जुटाया गया है तथा द्वितीयक

समंक प्रकाशित सरकारी सूचनाओं, प्रतिवेदनों, जर्नलों, पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं से जुटाया गया है। समंकों का उचित प्रकार से वर्गीकरण करके सारणीयन किया गया हैं तत्पश्चात् उचित प्रकार से विश्लेषण कर उचित प्रकार से निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया है।

परिकल्पना :

- रीवा जिले में औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं।
- रीवा जिले में अनेक प्राकृतिक व मानवीय साधन औद्योगिक विकास के लिये उचित मात्रा में उपलब्ध है।
- जिले में औद्योगिक विकास के लिये सार्थक प्रयास नहीं किये गये हैं।
- जिले में उत्साही उद्यमियों की कमी नहीं है इन्हें तकनीकी सहायता व वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

उद्देश्य :

- रीवा जिले में औद्योगिक विकास के संभावनाओं का पता लगाना।
- जिले के विकास के लिये समाज के प्रवुद्ध वर्ग एवं सरकार को जागृत करना।
- सरकारी एजेन्सियों से औद्योगिक विकास के नीति-निर्माण में सहायता पहुंचाना।
- जिले के औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक घरानों का घर आकर्षित करना।
- औद्योगिक समस्याओं का पता लगाना।
- समस्याओं के समाधान के लिये पता लगाना।
- आम जनता को श्रेष्ठ एवं उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध कराना।

विषय-विश्लेषण :

रीवा जिला एक विकासशील जिला है। यहां शैक्षणिक, चिकित्सीय, यातायात, संचार बीमा, बैंकिंग एवं विद्युत, सिंचाई आदि सुविधाओं से युक्त है। जिस कारण औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं हैं। यद्यपि जिले में लघु एवं कुटीर उद्योग बहुत पहले से संचालित है, किन्तु उनका आकार छोटा होने से उत्पादन क्षमता कम, रोजगार की कमी एवं विपणन गतिविधियों में कमी है। बड़े उद्योगों के लिये कच्चे माल के साथ-साथ औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध है, किन्तु सरकारी प्रयासों में कमी, उद्यमियों में औद्योगिक उत्साह की कमी एवं सामान्य जनता की जागरूकता का अभाव बड़े उद्योगों के विकास में बाधक रहे हैं।

रीवा जिले में चूना पथर की प्रचुरता के कारण यद्यपि सीमेन्ट उद्योग की स्थापना हो गई है, किन्तु वह पर्याप्त नहीं है और छोटे-बड़े उद्योग लगाये जा सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग जैसे- धान से चावल बनाना, गेहूं के आटे से बनी विभिन्न सामग्रियां, दूध से निर्मित वस्तुएं, तिलहन से तेल निकालने, आचार, पापड़, गन्ना इत्यादि आधारित उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। जिससे अनेक वस्तुओं का निर्माण होगा, उत्पादित वस्तुओं के भाव सर्से होंगे जो आम जनता के क्रय शक्ति में आयेंगे जो बेरोजगारी की समस्या दूर होगी, विपणन क्रियाएं तेज होगी एवं उत्पत्ति के साधनों की सक्रियता बढ़ेगी जिससे आर्थिक, सामाजिक विकास होगा, समाज के लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठेगा, लोगों का उपभोग बढ़ेगा एवं समग्र विकास के क्षेत्र में रीवा जिला अन्य विकसित जिलों के समान हो जायेगा तथा देश के औद्योगिक विकास में जिले का नाम अंकित हो जायेगा।

समस्याएं :

- औद्योगिक विकास में जनजीवन का अभाव।
- उपक्रम स्थापित करने के लिये प्रवर्तकों की कमी।
- लोगों में बचतें कम होने के कारण पूँजी निर्माण में बाधा।
- औद्योगिक इकाईयों की बढ़ती लागतें।

- सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में शिथिलता।
- जिले के आस-पास औद्योगिक गतिविधियों में कमी।
- मशीनों एवं यंत्रों की अनुउपलब्धता तथा मरम्मत व नवीनीकरण सुविधाओं का अभाव।
- विकसित विपणन का अभाव।
- लोगों में क्रय शक्ति की कमी।

सुझाव :

- औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये पर्याप्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- शासन को औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिये पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराना चाहिए।
- मशीनों, यंत्रों, भूमि, जल आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। ताकि औद्योगिक स्थापना में असानी हो।
- कच्चे माल व अप्रत्यक्ष सामग्रियों की पर्याप्त उपलब्धता बनानी चाहिए।
- उत्पादित माल के विक्रय के लिये समुचित बाजार उपलब्ध कराये जाने चाहिए।
- नये उद्यमियों को प्रोत्साहित करने एवं बाहरी उद्यमियों को भी जिले में उद्योग स्थापित करने के लिये आमंत्रित करना चाहिए।

निष्कर्ष :

रीवा जिले में शिक्षा एवं जागरूकता तेजी से बढ़ रही है, जिस कारण औद्योगिक इकाईयों की स्थापना में रुचि दिखाई दे रही है। यद्यपि पूँजी की कमी, मशीनों एवं यंत्रों का अभाव शासन का अपर्याप्त सहयोग आदि कारण मौजूद है। तथापि अन्य क्षेत्रों के विकास गतिविधियों के कारण रीवा जिले में भी औद्योगिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। रेल सेवा का होने के कारण रीवा के संबंध देश के विभिन्न औद्योगिक सम्पन्न स्थानों से सम्पर्क हो रहा है। जिस कारण औद्योगिक गतिशीलता बढ़ गई है और नये—नये व्यवसायी अपनी औद्योगिक इकाई की स्थापना के लिये उत्पादित हो रहे हैं। यदि शासकीय योजनायें इस हेतु कार्यान्वयन की जाय तो निश्चित रूप से जिला उद्योग प्रधान जिला बन सकता है। आशा है कि जिले के प्रतिनिधि इस उद्देश्य के अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे और रीवा जिले का पर्याप्त विकास होगा।

संदर्भ ग्रन्थ :

1. उद्यमिता विकास – प्रो. त्रिभुवन शुक्ल, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2015
2. व्यावसायिक वातावरण एवं उद्यमिता – गुप्ता एवं चतुर्वेदी, महावीर प्रकाशन, दिल्ली, 2013
3. लघु एवं कुटीर उद्योग (स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीज), एन.पी.सी.एस. (क्रियेटिव)–Creative Publication, 106-E कमला नगर, दिल्ली।
4. लेटेस्ट प्राफ़िटेबल होम कॉटेज एण्ड स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज – विकास अग्रवाल, हंस कान्सलटेन्सी ब्यूरो नई सड़क, दिल्ली।
5. समाचार पत्र एवं दूरदर्शन।
6. इन्टरनेट।
7. रीवा जिले का वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य एवं वर्ष 2020 की परिकल्पना, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, रीवा (म.प्र.)।



पूर्णिमा कुमारे

शोधार्थी, वाणिज्य विभाग, शास. शहीद केदारनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय,

मऊगंज, जिला रीवा (म.प्र.)